

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 818
उत्तर देने की तारीख: 07.02.2022

उत्तर-पूर्वी विश्वविद्यालयों में अवसंरचना और शैक्षणिक सुविधाएं

+818. कुमारी अगाथा के. संगमा:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने उत्तर-पूर्वी विश्वविद्यालयों में अवसंरचना और शैक्षणिक सुविधाओं में सुधार करने के लिए उन्हें अधिक शैक्षिक स्वायत्तता प्रदान करने का निर्णय लिया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजन के लिए कितनी राशि स्वीकृत और आवंटित की गई है;
- (ग) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान कॉलेजों और परिसर की सुविधाओं में सुधार के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के विश्वविद्यालयों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ड.) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने की संभावना है?

उत्तर
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (ड): चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, नए संस्थानों का निर्माण और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। हालाँकि, केंद्रीय सहायता की आवश्यकता को समझते हुए, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों की सहायता के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) की केंद्र प्रायोजित योजना जैसी विभिन्न योजनाओं को लागू किया है।

रूसा के विभिन्न घटकों के तहत राज्यों की विश्वविद्यालयों के संबंध में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सहायता की जाती है। असम में 2 विश्वविद्यालयों को पिछले तीन वर्षों (2018-19 से 2020-21) में 40 करोड़ रुपये की अनुमोदित निधि के साथ विश्वविद्यालय को अवसंरचना अनुदान (आईजीयू) के घटक के अंतर्गत सहायता के लिए अनुमोदित किया गया है। जहां तक कॉलेजों का संबंध है, पिछले तीन वर्षों (2018-19 से 2020-21) में पूर्वोत्तर राज्यों में कॉलेजों को अवसंरचना अनुदान (आईजीसी) घटक के अंतर्गत स्वीकृत कॉलेजों की संख्या का राज्य-वार विवरण नीचे दिया गया है:

राज्य का नाम	आईजीसी के तहत सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	कुल स्वीकृत निधि (रुपये करोड़ में)
अरुणाचल प्रदेश	4	8.00
असम	117	234.00
मणिपुर	10	20.00
मेघालय	12	24.00
मिजोरम	15	30.00
नागालैंड	5	10.00
सिक्किम	6	12.00
त्रिपुरा	7	14.00
कुल	176	352.00
